epaper
हिन्दुस्तान

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर बल

02/02/2022

नई दिल्ली | मदन जैड़ा

अगले साल के रक्षा बजट में भले ही ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई हो, लेकिन इसमें रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उपाय जरूर किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र के कुल आवंटन को 4.78 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ किया गया है। लेकिन, बड़ी घोषणा यह है कि रक्षा अनुसंधान के मद में खर्च की जाने वाली 25 फीसदी राशि निजी उद्योगों, स्टार्टअप तथा अकादमियों को भी प्रदान की जाएगी। मकसद यह है कि देश के लिए जरूरी मिलिट्री प्लेटफार्म और उपकरणों का विकास और निर्माण देश में ही हो।

रक्षा बजट की कुल राशि 5,25,166 करोड़ : चालू वर्ष का कुल रक्षा बजट 4,78,196 करोड़ है, जिसमें करीब 1.16 लाख करोड़ पेंशन के लिए निर्धारित है। जबकि रक्षा आधुनिकीकरण की राशि 1.36 करोड़ है। मंगलवार को पेश रक्षा बजट की कुल राशि 5,25,166 करोड़ है, जिसमें 1.19 करोड़ पेंशन और 1.52 करोड़ की राशि रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए रखी गई है।

आधुनिकीकरण के बजट में 12 फीसदी की बढ़ोतरी : पेंशन की राशि में साल-दर-साल बढ़ोतरी स्वभाविक है, लेकिन आधुनिकीकरण के बजट में 16,309 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी 12 फीसदी की है। हालांकि, पिछले साल यह बढ़ोतरी 19 फीसदी की हुई थी। इसी प्रकार यदि कुल रक्षा बजट की बात करें तो पिछले साल उसमें 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जो इस बार 9.8 फीसदी के करीब है। यदि राशि में देखें तो कुल 46,970 करोड़ रुपये इस बार अधिक मिले हैं।

68 फीसदी रक्षा उपकरण देश में खरीदे जाएंगे : सरकार पिछले कुछ समय से रक्षा खरीद के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है। इस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुल रक्षा खरीद की 68 फीसदी खरीद देश में ही निर्मित सामग्री की करने की घोषणा की है। पिछले बजट में यह सीमा 58 फीसदी की थी। इससे ज्यादा से ज्यादा खरीद देश में बने रक्षा सामानों की हो सकेगी।

5.25
लाख करोड़
बजट
2022-23 में

4.78
लाख करोड़ था
रक्षा बजट
2021-22 में

25 फीसदी शोध राशि निजी उद्योगों-स्टार्टअपको मिलेगी

रक्षा शोध पर देश में जो धनराशि खर्च होती थी, ज्यादातर वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को ही दी जाती थी। लेकिन, बजट में घोषणा की गई है कि 25 फीसदी शोध राशि निजी उद्योगों, स्टार्टअप एवं अकादमियों को प्रदान की जाएगी ताकि वे भी रक्षा तकनीकों का विकास कर सकें और बाद में उनका निर्माण भी करें। वे डीआरडीओ के साथ मिलकर भी शोध कर सकेंगे। दरअसल, सरकार ने पिछले एक साल के दौरान करीब 200 से अधिक रक्षा तकनीकों को देश में ही निर्मित करने का निर्णय लिया है।

यह निजी क्षेत्र के सहयोग से ही संभव है।